विकास प्रताप सिंह एवं अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

(2013 की सिविल अपील संख्या 5318-19 आदि)

9 जुलाई 2013

(न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू और न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर)

सेवा कानूनः

भर्ती/चयन - प्रतियोगी परीक्षा - सफल अभ्यर्थियों की योग्यता सूची के अनुसार नियुक्ति - मुख्य परीक्षा के प्रश्नों में दोष/गलतियों की शिकायतें विशेषज्ञ समिति ने पाई दोष/त्रुटि - सभी अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं का चयनात्मक पुनर्मूल्यांकन - संशोधित योग्यता सूची निकाली गई - संशोधित सूची में पहली मेरिट सूची के आधार पर नियुक्त किए गए 26 उम्मीदवारों का नाम नहीं था - संशोधित मेरिट सूची की वैधता को चुनौती देने वाली 26 उम्मीदवारों की रिट याचिका - उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी - माना गयाः पुनर्मूल्यांकन का निर्णय वैध था और इससे 26 उम्मीदवारों या संशोधित मेरिट सूची में चयनित उम्मीदवारों पर कोई

पूर्वाग्रह प्रभाव नहीं पड़ा - लेकिन चूंकि उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के तहत 3 साल की सेवा प्रदान की है और चूंकि 26 अभ्यर्थी अनियमितता के लिए जिम्मेदार नहीं थे, इसलिए उनकी नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती - 26 अभ्यर्थियों को संशोधित मेरिट सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा वे पहली योग्यता सूची के अनुसार उनकी नियुक्ति के आधार पर बकाया वेतन वरिष्ठता या कोई अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे।

अध्यक्ष, जे और के राज्य शिक्षा बोर्ड बनाम फ़याज़ अहमद मलिक और अन्य, (2000) 3 एससीसी 59 2000 (1) एससीआर 402; साहिती और. अन्य. बनाम चांसलर, डॉ. एन.टी.आर. स्वास्थ्य विज्ञान और अन्य विश्वविद्यालय, (2009) 1 एससीसी 59:2008 (14) एससीआर 1032; भारत संघ और अन्य बनाम एम. भास्करन 1995 पूरक (4) एससीसी 100:1995 (4) पूरक एससीआर 526; विनोदन टी. ए और अन्य बनाम कालीकट विश्वविद्यालय और अन्य (2002) 4 एससीसी 726:2002 (3) एससीआर 530; यूपी राज्य बनाम नीरज अवस्थी और अन्य (2006) 1 एससीसी 667:2005 (5) पूरक एससीआर 906; गिरजेश श्रीवास्तव और अन्य बनाम म.प्र. राज्य और अन्य (2010) 10 एससीसी 707:2010 (12) एससीआर 839; भारत संघ (यूओआई) और अन्य बनाम नरेंद्र सिंह

(2008) 2 एससीसी 750: 2007 (13) एससीआर 504; गुजरात राज्य उप कार्यकारी अभियंता संघ बनाम गुजरात राज्य और अन्य 1994 सप्लीमेंट (2) एससीसी 591; बुद्धि नाथ चैधरी और अन्य बनाम अखिल कुमार और अन्य (2001) 2 एससीआर 18; एमएस मुधोल (डॉ.) और अन्य बनाम एस.डी. हलेगकर और अन्य (1993) प्प् एलएलजे 1159 एससी त्रिदीप कुमार डिंगल और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2009) 1 एससीसी 768: 2008 (15) एससीआर 194 - पर निर्भर किया। गई जिला कलेक्टर और अध्यक्ष, विजयनगरम सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी, विजयनगरम और अन्य बनाम एम. त्रिपुरा सुंदरी देवी (1990) 3 एससीसी 655: 1990 (2) एससीआर 559; पी. चेंगलवरैया नायडू बनाम जगन्नाथ और अन्य (1994) 1 एससीसी 1: 1993 (3) पूरक एससीआर 422 - संदर्भित किया।

मक्सीकम 'फ्रैंस एट जूस नुनक्वाम कोहिबिटेंट' की प्रयोज्यता.

केस कानून संदर्भः

2000 (1) एससीआर 402	भरोसा	पैरा 16
2008 (14) एससीआर 1032	भरोसा	पैरा 16
1990 (2) एससीआर 559	उल्लेख	पैरा 20

1993 (3) पूरक एससीआर 422,	उल्लेख किया	पैरा 20
1995 (4) पूरक एससीआर 526	भरोसा किया	पैरा 20
2002 (3) एससीआर 530	भरोसा किया	पैरा 20
2005 (5) पूरक एससीआर 906	भरोसा किया	पैरा 20
2010 (12) एससीआर 839	भरोसा किया	पैरा 21
2007 (13) एससीआर 504	भरोसा किया	पैरा 22
1994 सप्लीमेंट (2) एससीसी 591	भरोसा किया	पैरा 23
(2001) 2 एससीआर 18	भरोसा किया	पैरा 24
(1993) II एलएलजे 1159 एससी	भरोसा किया	पैरा 24
2008 (15) एससीआर 194	भरोसा किया	पैरा 24

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2013 की सिविल अपील संख्या 5318-5319

बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 2009 की रिट याचिका संख्या 4229 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 06.09.2011 से

साथ में

2013 की सिविल अपील संख्या 5318-5319 (2011 की एस.एल.पी. (सी) संख्या 26341 26342)

2013 की सी.ए. संख्या 5320 और 2011 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 433 2013 की सी.ए. संख्या 5320 में।

एस.के. दुबे, मुकुल रोहतगी, समीर श्रीवास्तव, कुणाल वर्मा, अतुल झा, संदीप झा, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, अपूर्व कुरुप (सी.डी. सिंह के लिए), संजीब पाणिग्रही, एल. निधिराम शर्मा (सिद्धार्थ चैधरी के लिए) पक्षकारान के लिए उपस्थित।

न्यायालय का आदेश न्यायमूर्ति एच.एल. दतु द्वारा सुनाया गया।

1. सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलों का समूह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा 2009 की रिट याचिका संख्या 3087, 3204 और 4229, दिनांक 06.09.2011 में पारित समान निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जहां पर और जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया और प्रत्यर्थी-राज्य छत्तीसगढ़ में सूबेदारों, प्लेटून कमांडरों और उप-निरीक्षकों के पदों के लिए मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं के चयनात्मक पुनर्मूल्यांकन के

बाद निकाली गई संशोधित मेरिट सूची की पुष्टि की।

3. हमारे समक्ष अपीलकर्ता (एसएलपी (सी) संख्या 26341-26342 ऑफ 2011 और 26349 ऑफ 2011 में) वे 26 उम्मीदवार हैं जो छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (संक्षेप में प्रत्यर्थी बोर्ड) द्वारा पहली मेरिट सूची को रद्द करने और दूसरी संशोधित मेरिट सूची को फिर से निकालने से व्यथित हैं। जहां पर उपरोक्त पदों पर उनकी नियुक्तियाँ रद्द कर दी गई हैं।

4. तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं

18.09.2006 को, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रत्यर्थी राज्य में सूबेदारों, प्लेटून कमांडरों और उप-निरीक्षकों के 380 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला एक विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त उद्देश्य के लिए, प्रारंभिक परीक्षा 24.12.2006 को आयोजित की गई थी और सफल उम्मीदवारों को क्रमशः 04.02.2007 और 05.02.2007 को पेपर प् और प्प् के रूप में दो भागों में आयोजित मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया था। शारीरिक परीक्षण और व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करने के बाद, उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची 08.04.2008 को प्रकाशित की गई, जिसमें सभी अपीलकर्ताओं का चयन हुआ। उक्त मेरिट सूची के आधार पर, अपीलकर्ताओं सहित चयनित उम्मीदवारों को 21.08.2008 और 15.09.2008 के बीच विभिन्न तिथियों पर नियुक्ति पत्र

जारी किए गए थे। इस बीच, पुलिस महानिरीक्षक और प्रत्यर्थी-बोर्ड को मुख्य परीक्षा पत्रों के कई प्रश्नों में दोष/गलतियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुईं। प्रत्यर्थी-बोर्ड ने शिकायतों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। दोनों पेपरों की जांच करने पर, दोषों/गलतियों के दो सेट देखे गएः (ए) पेपर प्प् में आठ प्रश्न गलत थे और (बी) पेपर प्प् के अन्य आठ प्रश्नों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए मॉडल उत्तर गलत थे। प्रत्यर्थी-बोर्ड ने पेपर प्प् में आठ प्रश्नों के पहले सेट को हटाने और पेपर प् और प्प् में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए सही मॉडल उत्तर कुंजी तैयार करने का निर्देश दिया और तदनुसार उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया।

27.06.2009 को एक नई संशोधित मेरिट सूची प्रकाशित की गई थी जिसमें छब्बीस अपीलकर्ताओं के नाम बिल्कुल भी नहीं थे और तदनुसार, प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा अपीलकर्ताओं की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी।

5. संशोधित मेरिट सूची के प्रकाशन के समय, अपीलकर्ता पहले से ही पहली सूची में चयनित अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे। संशोधित योग्यता सूची के मद्देनजर उपरोक्त नियुक्ति को रद्द करने से व्यथित अपीलकर्ताओं ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें प्रत्यर्थी-बोर्ड द्वारा पुनर्मूल्यांकन के निर्णय के

आधार पर संशोधित योग्यता सूची की वैधता को मनमाना और तर्कहीन होने के कारण चुनौती दी गई, इसलिए उक्त सूची को रद्द करने की आवश्यकता है।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं पर विचार करते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया था जिसमें प्रत्यर्थी-राज्य को अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई भी कठोर कदम नहीं उठाने और उन्हें अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि इस मामले में सार्वजनिक महत्व का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ है और इसलिए, सार्वजनिक महत्व के कानून के निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करने और निर्णय लेने के अनुरोध के साथ मामले को खण्डपीठ को भेज दिया गया।

> "क्या वीवाईएपीएम (प्रत्यर्थी-बोर्ड) चयन सूची के प्रकाशन और प्रश्नों के मूल्यांकन के आधार पर नियुक्ति आदेश पारित करने के बाद, उत्तरों को संपादित और पुनः तैयार करने के बाद उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन करने की कवायद कर सकता है और अभ्यर्थियों की नई भर्ती के लिए दूसरी चयन सूची, पहली चयन सूची को रद्द कर तैयार कर सकता है ?

7. खण्डपीठ ने मामले के गुणावगुण पर विस्तार से विचार किया है

और दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का विश्लेषण किया। खण्डपीठ ने मुख्य परीक्षा के पैटर्न पर ध्यान दिया जिसमें दो अलग-अलग पेपर शामिल किए गए हैं पेपर प i में वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल हैं - क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में 7 और 4 और पेपर प्प् में सामान्य ज्ञान के 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा, प्रत्यर्थी-बोर्ड द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने पेपर i और ii दोनों की जांच की और केवल पेपर ii के आठ गलत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और पेपर के मॉडल उत्तर कुंजी में अन्य आठ प्रश्नों के मॉडल उत्तरों के संबंध में अनियमितताएं पाईं। प्रत्यर्थी-बोर्ड ने नए मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर पेपर ii और पेपर i के केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन किया और इस तरह के पुनर्मूल्यांकन पर पेपर प्प् के केवल सोलह प्रश्नों और उत्तरों में हस्तक्षेप किया गया। आठ गलत प्रश्नों को हटा दिया गया और उनके अंक प्रत्यर्थी-बोर्ड के परीक्षा आचरण नियमों (संक्षेप में "नियम") के खंड 14 और अन्य आठ प्रश्नों के अनुसार आनुपातिक आधार पर वितरित किए गए, जिनके पहले मॉडल उत्तर कुंजी में उत्तर गलत थे, उनका नए मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया गया और तदनुसार अंक दिए गए। खण्डपीठ ने देखा है कि चूंकि पुनर्मूल्यांकन किए गए सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के थे और केवल एक सही उत्तर के लिए निश्चित अंक थे, इसलिए पुनर्मूल्यांकन

के दौरान अंकन योजना में अंतर या पूर्वाग्रह की संभावना पैदा नहीं होती है और इसलिए यह निष्कर्ष निकाला कि कोई अनियमितता या यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी-बोर्ड द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन के प्रकार और तरीके में अवैधता नहीं है और पुनर्मूल्यांकन का उक्त निर्णय उचित, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण था और इससे उम्मीदवारों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ और इसलिए जब तक यह मामला मनमाना, अनुचित या दुर्भावनापूर्ण न पाया जाए तब तक इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उपरोक्त निष्कर्ष के परिणामस्वरूप, खण्डपीठ ने पहली सूची के आधार पर अपीलकर्ताओं की नियुक्तियों को रद्द करना उचित समझा और तदनुसार रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

8. यह उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय और आदेश की सत्यता या अन्यथा है जो विशेष अनुमति द्वारा इन अपीलों में हमारे सामने है।

9. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री पीपी राव और श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुना और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित श्री मुकुल रोहतगी और श्री पीएस पटवालिया वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुना और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

10. श्री राव का कहना है कि किसी भी वैधानिक प्रावधानों के अभाव में उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने और बाद में अपीलकर्ताओं की नियुक्ति को रद्द करने वाली संशोधित मेरिट सूची के प्रकाशन का प्रत्यर्थी-बोर्ड का निर्णय मनमाना है और अपीलकर्ताओं के प्रति पूर्वाग्रह है। उन्होंने आगे कहा कि गलत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करने वाले नियमों के खंड 14 का दायरा व्यापक है और इसमें परीक्षा प्रश्नों के मॉडल उत्तर गलत होने जैसी अनिवार्यताएं शामिल हैं और इसलिए, प्रत्यर्थी-बोर्ड को निर्देश देने के बजाय -उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उक्त वैधानिक प्रावधान के अनुपालन में किया जाना चाहिए।

11. इसके विपरीत, वरिष्ठ वकील श्री रोहतगी का कहना था कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तीन शैलियों को प्रभावित किया: सबसे पहले, पेपर प्प् में आठ प्रश्न जो गलत पाए गए; दूसरे, पेपर प्प् के आठ प्रश्न जिनके उत्तर मॉडल उत्तर कुंजी में गलत पाए गए और तीसरा, पेपर प् के वे प्रश्न जिनके लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति से पहले कोई मॉडल उत्तर प्रदान नहीं किए गए थे। उनका कहना था कि आठ प्रश्नों का पहला सेट हटा दिया गया था और नियमों के खंड 14 के अनुसार आनुपातिक आधार पर अंक दिए गए थे। आठ प्रश्नों के दूसरे सेट का संशोधित मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया गया और

पेपर । में प्रश्नों के तीसरे सेट का, सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के, का विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए मॉडल उत्तर कुंजी की सहायता से पुनर्मूल्यांकन किया गया। उनका कहना है कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के प्रत्यर्थी-बोर्ड के निर्णय ने अपीलकर्ताओं के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया है, बल्कि वास्तव में उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं के पहले मूल्यांकन में अनियमितताओं की पहचान की और उन्हें सुधारा है और इसलिए, निर्णय को मनमाना, प्रतिशोधपूर्ण और मनमौजी नहीं कहा जा सकता।

12. इन अपीलों में हमारे विचार के लिए यह है कि क्या उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के निर्देश में प्रत्यर्थी-बोर्ड के निर्णय ने दिनांक 08.04.2008 की पहली मेरिट सूची के लिए नियुक्त अपीलकर्ताओं पर कोई पूर्वाग्रह पैदा किया है।

13. शुरुआत में, विद्वान वरिष्ठ वकीलों द्वारा की गई दलीलों के गुणावगुण पर गौर करने से पहले, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और पुनर्मूल्यांकन योजना/नियमों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

14. यह विवाद में नहीं है और न ही इस पर विवाद किया जा सकता है कि पुनर्मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, गलत पाए गए आठ प्रश्नों को हटा दिया गया था और उनके अंक नियमों के खंड 14 के अनुसार आनुपातिक

आधार पर सही ढंग से निम्नानुसार आवंटित किए गए।

"खंड 14. गलत (दोषपूर्ण) वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न, उसका रद्दीकरण और उसके बदले में आवंटित किए जाने वाले अंक। परीक्षा के बाद छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) प्रत्येक प्रश्न की जांच विषय विशेषज्ञ से कराता है। यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण करने पर प्रश्न दोषपूर्ण/गलत पाया जाता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न अस्वीकृत किये जा सकते हैं.

i) यदि प्रश्न की संरचना गलत है;

ii) उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से यदि एक से अधिक विकल्प सही हैं।

iii) यदि कोई विकल्प सही नहीं है।

iv) यदि किसी प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में अंतर है जिसके कारण दोनों का अलग-अलग अर्थ निकाला जाता है और एक सही उत्तर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

अ) यदि कोई अन्य मुद्रण त्रुटि है जिसके कारण सही उत्तर सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है या एक से अधिक विकल्प सही हैं। विषय विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर प्रश्न अस्वीकार किये जाने पर ऐसे प्रश्नों पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा अभ्यर्थियों को विशेष प्रश्नपत्र में प्राप्त अंकों के अनुपात में अंक दिये जायेंगे। चाहे अस्वीकृत/रद्द प्रश्न का प्रयास किया गया है या नहीं। जिन प्रश्न पत्रों के प्रश्न निरस्त किये गये हैं, उनकी मूल्यांकन प्रक्रिया इस प्रकार होगी, यदि किसी प्रश्न पत्र में 100 प्रश्नों में से दो प्रश्न निरस्त किये जाते हैं तथा मूल्यांकन के उपरान्त अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में से 81 अंक प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में अंकों की गणना (81'100)/100-2= 82.65 के रूप में की जाएगी जिसके आधार पर योग्यता का निर्धारण किया जाएगा।''

अन्य आठ प्रश्न जिनके उत्तर पहले की मॉडल उत्तर कुंजी में गलत पाए गए थे, उनका संशोधित मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया गया। पेपर प् में, प्रत्यर्थी-बोर्ड द्वारा जांच के बाद पहली बार तैयार की गई मॉडल उत्तर कुंजी की सहायता से केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों

का पुनर्मूल्यांकन किया गया और पर्वयक्षक को प्रदान किया गया।

15. खंड 14 के समावेशी प्रावधान होने और इस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में होने वाली समान अनियमितताओं को शामिल करने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करने के संबंध में श्री राव द्वारा दी गई दलील हमें समझाने में विफल रही। खंड 14 उन पांच विशिष्ट उदाहरणों पर विचार और सूचीबद्ध करता है जिनमें परीक्षा पत्र में प्रश्न ही गलत है और इस प्रकार संभवतः किसी भी सही उत्तर के लिए मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में यह ऐसे गलत प्रश्नों को हटाने और उनके लिए आवंटित अंकों के आनुपातिक वितरण का प्रावधान करता है।

उक्त नियम स्पष्ट है और केवल प्रश्नों में विसंगतियों की स्थिति में ही प्रक्रिया का प्रावधान करता है। यह उत्तरों/मॉडल उत्तरों में त्रुटियों को शामिल करने के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता है और इसलिए, प्रतिवादी-बोर्ड ने खंड 14 के अनुसार केवल आठ गलत प्रश्नों का सही ढंग से पुनर्मूल्यांकन किया है।

16. उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का निर्णय लेने में प्रत्यर्थी-बोर्ड के औचित्य के संबंध में, हमारा विचार है कि प्रत्यर्थी-बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय है जिसे विशेषज्ञों की मदद से निष्पक्ष और उचित तरीके से सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के उचित संचालन का कर्तव्य सौंपा

गया है। यदि मूल्यांकन प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उस संबंध में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन पर निर्णय लेने का अधिकार है। (देखेंः अध्यक्ष, जे एंड के स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाम फेयाज अहमद मलिक और अन्य , (2000) 3 एससीसी 59 और साहिती और अन्य बनाम चांसलर, डॉ. एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड अन्य , (2009) 1 एससीसी 599) यह स्थापित कानून है कि यदि मूल्यांकन में अनियमितताओं को देखा जा सके और विशेष रूप से सही किया जा सके और अयोग्य चयनित उम्मीदवारों की पहचान की जा सके और उनके स्थान पर योग्य उम्मीदवारों को चयन सूची में शामिल किया जा सके, तो यह नहीं कहा जाएगा कि पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में कोई अवैधता है। प्रत्यर्थी-बोर्ड ने इस प्रकार मूल्यांकन प्रक्रिया में व्याप्त अनियमितताओं की पहचान की और आठ प्रश्नों के उत्तर गलत थे और आठ गलत प्रश्नों को हटाकर और आनुपातिक आधार पर उनके अंको के आवंटन के संबंध में पुनर्मूल्यांकन की विधि को नियोजित करके इसे ठीक किया। उक्त निर्णय को मनमाना नहीं कहा जा सकता। यदि व्यक्तिपूरक उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन किया गया होता तो वास्तव में अनुचित पूर्वाग्रह पैदा होता, जो यहां मामला नहीं है।

17. उपरोक्त के मद्देनजर, हमारी सुविचारित राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रत्यर्थी-बोर्ड द्वारा पुनर्मूल्यांकन का निर्णय एक वैध निर्णय था जिसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि इससे कोई पूर्वाग्रह पैदा हुआ हो, चाहे जो भी हो , या तो अपीलकर्ताओं को या संशोधित मेरिट सूची में चयनित उम्मीदवारों को और इसलिए, हमें उपरोक्त सीमा तक उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश में कोई त्रुटि/खामी नहीं दिखती है।

18. यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के मद्देनजर अपीलकर्ताओं ने अब अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और तीन साल से अधिक समय से सेवा में हैं। इसलिए एकमात्र प्रश्न जो हमारे विचार और निर्णय के लिए बचा हुआ है, वह यह है कि क्या प्रशिक्षण प्राप्त करने और अपनी पोस्टिंग के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद उक्त 26 अपीलकर्ताओं को संशोधित मेरिट सूची के आधार पर व उनकी नियुक्ति रद्द करने के आधार पर सेवा से बाहर कर दिया जाना चाहिए।

19. श्री राव प्रस्तुत ने प्रस्तुत किया कि इन अपीलकर्ताओं के मामले पर इस न्यायालय द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उचित रूप से आयोजित प्रतिस्पर्धी परीक्षा के आधार पर

अपीलकर्ताओं की नियुक्ति किसी भी कदाचार या अन्य बाहरी विचार या गलत बयानी से प्रभावित नहीं हुई है। उनका हिस्सा. सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने और तीन साल से अधिक समय तक प्रत्यर्थी-राज्य की सेवा करने के बाद 26 अपीलकर्ताओं को सेवा से बाहर करने से उन्हें अनुचित कठिनाई होगी और उनका जीवन और करियर बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उनमें से आठ अपीलकर्ताओं को जीवन और आजीविका के मामले में अपूरणीय क्षति होगी, जो अब अधिक उम्र के हो गए हैं और बाद की परीक्षाओं में बैठने का अवसर भी खो चुके हैं। वह राजेश कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य अन्य 2013(3) SCALE 393 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करेंगे जिसमें इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी-राज्य को सही मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है और ऐसे उम्मीदवारों के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जो बाद में गलत मूल्यांकन के आधार पर नियुक्त होने और काफी लंबे समय तक राज्य में सेवा करने के बाद, उन्हें पुनर्मूल्यांकन के बाद निकाली गई नई योग्यता सूची में जगह नहीं मिलेगी और उन्होंने प्रत्यर्थी-राज्य को ऐसे उम्मीदवारों को बाहर करने के खिलाफ निर्देश दिया और आगे कहा कि उन्हें ताजा मेरिट सूची में सबसे नीचे रखा जाए।

20. प्राचीन कहावत फ्रौस एट जूस नुनक्वाम कोहैबिटेंट (धोखाधड़ी और न्याय कभी एक साथ नहीं ने सदियों से कभी अपना आपा नहीं खोया है और यह सेवा कानून न्यायशास्त्र की आत्मा और शरीर में बसा हुआ है। यह स्थापित कानून है कि किसी ऐसे उम्मीदवार को उक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जिसने धोखाधड़ी, शरारत, गलत बयानी या दुर्भावना से रोजगार प्राप्त किया है। (देखेंः जिला कलेक्टर और अध्यक्ष, विजयनगरम सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी, विजयनगरम और अन्य बनाम एम. त्रिपुरा सुंदरी देवी, (1990) 3 एससीसी 655, पी. चेंगलवरया नायडू बनाम जगन्नाथ और अन्य , (1994) 1 एससीसी 1 और भारत संघ और अन्य बनाम एम. भास्करन , 1995 सप्लि. (4) एससीसी 100) यह भी स्थापित कानून है कि किसी पद पर गलत तरीके से नियुक्त व्यक्ति को मेधावी और योग्य उम्मीदवारों के हितों को खतरे में डालकर गलत नियुक्ति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां नियुक्त व्यक्ति की ओर से बिना किसी गलती के गलत या अनियमित नियुक्ति की जाती है और ऐसी त्रुटि या अनियमितता

का पता चलने पर नियुक्ति को समाप्त कर दिया जाता है, इस न्यायालय ने सद्भावना सहित विभिन्न कारकों के प्रकाश में ऐसी नियुक्ति में उम्मीदवार और ऐसी नियुक्ति के बाद उम्मीदवार की सेवा अवधि के संबंध में

सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। (देखेंः विनोदन टी. और अन्य बनाम कालीकट विश्वविद्यालय और अन्य , (2002) 4 एससीसी 726; यूपी राज्य बनाम नीरज अवस्थी और अन्य (2006) 1 एससीसी 667)

21. गिरजेश श्रीवास्तव और अन्य बनाम एमपी राज्य और अन्य , (2010) 10 एससीसी 707 में उच्च न्यायालय ने चयन प्रक्रिया निर्धारित करने वाले नियम को अमान्य कर दिया था, जिसमें तीन साल के लंबे गैर-औपचारिक शिक्षण अनुभव वाले उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत अनुग्रह अंक और आयु में छूट दी गई थी। जिसके परिणामस्वरूप उक्त नियम के तहत औपचारिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षक के रूप में नियुक्त कई उम्मीदवार बाहर हो गए। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से सहमति जताते हुए यह ध्यान में रखा कि काफी समय के बाद नियुक्ति में अनियमितताओं को सुधारने पर नियुक्ति रद्द करने का आदेश कई उम्मीदवारों की आर्थिक सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और इस प्रकार देखा गयाः

> ‘‘उनमें से अधिकांश पहले अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में पढ़ा रहे थे, जहां से उन्होंने विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने के लिए इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना पिछला रोजगार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए छोड़ दिया था कि

उनके तीन साल लंबे शिक्षण अनुभव के लिए, वर्तमान चयन में साक्षात्कार प्रक्रिया उन्हें 25 प्रतिशत का अनुग्रह अंक प्रदान कर रही थी। इसमें उन्हें उनकी उम्र के संबंध में 8 साल की छूट भी दी गई थी। अब, यदि वे उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप अपनी नौकरी खो देते हैं, तो वे प्रभावी रूप से बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि वे गैर-औपचारिक शिक्षा केंद्रों में अपनी पिछली नौकरियों पर भी वापस नहीं लौट सकते हैं, जिन्हें तब से समाप्त कर दिया गया है। इससे कई परिवारों की आर्थिक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। उनमें से अधिकांश 35-45 वर्ष की आयु के बीच हैं, और उनके लिए दूसरी नौकरी खोजने की संभावनाएँ कम हैं। उनमें से कुछ वास्तव में उच्च न्यायालय द्वारा उनकी नियुक्ति को रद्द करने के समय अपने वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे।''

इसलिए, उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने अमान्य नियम के तहत नियुक्त उम्मीदवारों को बाहर न करने का निर्देश दिया।

22. भारत संघ (यूओआई) और अन्य बनाम नरेंद्र सिंह , (2008) 2

एससीसी 750 में इस न्यायालय ने उस कर्मचारी की उम्र पर विचार किया जिसे गलती से पदोन्नत किया गया था और पदोन्नत पद पर उसकी सेवा की अवधि और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होने के कारक पर विचार किया गया और निम्नानुसार देखा गया:

> ''हालाँकि, प्रत्यर्थी की ओर से अंतिम प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्यर्थी पिछले सत्रह वर्षों से वरिष्ठ लेखाकार (कार्यात्मक) के पद पर कार्यरत है। वह सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, यहां तक कि अब कुछ ही दिन बचे हैं। वह इस महीने के अंत यानी 31 दिसंबर, 2007 तक सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुंच जाएगा। इसलिए, हमारे विचार में, प्रत्यर्थी को बहुत कम अवधि के लिए लेखाकार के पद पर वापस भेजना उचित नहीं होगा। इसलिए, हम अपीलकर्ताओं को निर्देश देते हैं कि वे प्रत्यर्थी को वरिष्ठ लेखाकार (कार्यात्मक) के रूप में तब तक जारी रखें जब तक कि वह सेवानिवृत्ति की आयु तक नहीं पहुंच जाता, यानी 31 दिसंबर, 2007 तक। साथ ही, हम मानते हैं कि चूंकि अधिकारियों की कार्यवाही विधि के अनुसार थी नियमों के अनुसार, उप महालेखाकार द्वारा प्रत्यर्थी की

पदोन्नति को रद्द करने और उसे लेखाकार के मूल पद पर वापस करने का आदेश कानूनी और वैध था और प्रत्यर्थी को वरिष्ठ लेखाकार के रूप में पदोन्नत नहीं किया जा सकता था, उसे लेखाकार के रूप में सेवानिवृत्त माना जाएगा, न कि वरिष्ठ लेखाकार (कार्यात्मक) के रूप में और उसके पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ पूरे समय लेखाकार के रूप में मानकर उसके अनुसार तय किए जाएंगे। उपरोक्त कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। यद्यपि प्रत्यर्थी को सेवानिवृत्ति की आयु अर्थात 31 दिसंबर, 2007 तक वरिष्ठ लेखाकार (कार्यात्मक) के पद पर बने रहने की अनुमति है और उस क्षमता में उसे भुगतान किया गया वेतन वसूल नहीं लिया जाएगा, उसके सेवानिवृत्ति लाभ वरिष्ठ अकाउंटेंट (कार्यात्मक) के रूप में तय नहीं किए जाएंगे। लेकिन अकाउंटेंट के रूप में। मामले के इन तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।"

23. गुजरात राज्य उप कार्यकारी अभियंता संघ बनाम गुजरात राज्य और अन्य,1994 सप्लिमेंट (2) एससीसी 591 में इस न्यायालय ने हालांकि एक निष्कर्ष दर्ज किया कि 'प्रतीक्षा सूची के तहत दी गई नियुक्तियां कानून

के अनुसार नहीं थीं, लेकिन सेवा की अवधि (पांच वर्ष और अधिक) को देखते हुए ऐसी नियुक्तियों को अपास्त करने से इन्कार कर दिया।

24. बुद्धि नाथ चैधरी और अन्य बनाम अखिल कुमार और अन्य, (2001) 2 एससीआर 18, में भले ही नियुक्तियों को अनुचित माना गया था, इस न्यायालय ने इस आधार पर नियुक्तियों में गड़बड़ी नहीं की कि पदधारियों ने कई वर्षों तक काम किया था और अनुभव प्राप्त किया था और देखाः

“हमने ऐसे चयनित उम्मीदवारों पर न्यायसंगत विचार किया है जिन्होंने लंबे समय तक पदों पर काम किया है।”(देखें एमएस मुधोल (डॉ.) और अन्य बनाम एसडी हलेगकर और अन्य , (1993) प्प् एलएलजे 1159 एससी और त्रिदीप कुमार डिंगल और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य , (2009) 1 एससीसी 768)

25. स्वीकार्य रूप से, वर्तमान मामले में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के मामले में प्रत्यर्थी-बोर्ड द्वारा की गई त्रुटि के लिए अपीलकर्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि उन्हें नियुक्ति के लिए कोई धोखाधड़ी या गलत बयानी करते हुए नहीं पाया गया है, न

ही पहली मेरिट सूची में त्रुटिपूर्ण मॉडल उत्तर कुंजी या विशिष्ट परिणाम की तैयारी का योगदान है। यदि इसके विपरीत मामला होता, तो पुनर्मूल्यांकन पर उनके निष्कासन को उचित ठहराया जाता और उनकी सेवा की लंबाई के बावजूद उन्हें इस न्यायालय से किसी भी सहानुभूति से वंचित किया जाता।

26. हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और तीन साल से अधिक समय से प्रत्यर्थी-राज्य की कुशलतापूर्वक सेवा कर रहे हैं और निस्संदेह उनकी समाप्ति से न केवल अपीलकर्ताओं और उनके आश्रितों की आर्थिक सुरक्षा प्रभावित होगी बल्कि उनके करियर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। . यह उन अपीलकर्ताओं के लिए अत्यधिक अन्यायपूर्ण और घोर अन्याय होगा जो उत्तर पुस्तिकाओं के गलत मूल्यांकन के कारण निर्दोष नियुक्त व्यक्ति हैं। हालाँकि, सेवा में उनके बने रहने से न तो अपीलकर्ताओं को कोई अनुचित लाभ मिलना चाहिए और न ही संशोधित योग्यता सूची के आधार पर चयनित उम्मीदवारों पर अनुचित प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

27. तदनुसार, हम प्रत्यर्थी-राज्य को संशोधित योग्यता सूची में अपीलकर्ताओं को उक्त सूची में सबसे नीचे रखते हुए नियुक्त करने का निर्देश देते हैं। जिन उम्मीदवारों ने नियुक्ति के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु

पार कर ली है, उन्हें उपयुक्त आयु में छूट दी जाएगी।

28. हम स्पष्ट करते हैं कि उनकी नियुक्ति सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए नई नियुक्ति होगी जो अपीलकर्ताओं को उनकी पिछली नियुक्ति के आधार पर किसी भी पिछले वेतन, वरिष्ठता या किसी अन्य लाभ का हकदार नहीं बनाएगी।

29. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश उपरोक्त सीमा तक संशोधित माना जाएगा। अपीलें निस्तारित की जाती है।

30. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

2013 की सिविल अपील संख्या 5320 (2011 की एसएलपी (सी) संख्या 26349) में 2011 की अवमानना याचिका संख्या 433

विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 26341-26342 और विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 26349 वर्ष 2011 में पारित आदेशों के मद्देनजर इस अवमानना याचिका में हमारे विचार और निर्णय के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तदनुसार अवमानना याचिका निरर्थक होने के कारण खारिज की जाती है। तदनुसार आदेश दिया गया।

अपील और अवमानना याचिका निस्तारित की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ज्योति देवी शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।